

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

# तिब्बत देश



निर्वाचित तिब्बती संसद के स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल और  
उपाध्यक्ष डोलमा छेरिंग तेखांग ने रणनीतिक योजना  
2023-2026 दस्तावेज का विमोचन किया।

# तिब्बत देश

अगस्त, 2023, वर्ष : 44 अंक : 08

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथों में



केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का ७७वां स्वतंत्रता दिवस मनाया

प्रधान संपादक  
जमयंग दोरजी, थुप्तेन रिन्जीन

सलाहकार संपादक  
प्रो. श्यामनाथ मिश्र, डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक  
तेनजिन जोरदेन

वितरण प्रबंधक  
छोन्ची छरिंग, ताशी देकि

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :

भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र  
एच - १० लाजपत नगर - ३  
नई दिल्ली - ११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचारों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें।

## समाचार -

## समाचार -

- एसईई लर्निंग मुद्देपर विचार- विमर्श के लिए प्रतिभागियों के साथ बैठक 1
- केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का ७७वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 2
- 'वन चाइना पॉलिसी' का तिब्बतसे कोई लेना-देना नहीं है: सिक्योंगपेन्पा छेरिंग 3
- अपने कैदी भाई से मिलने पहुंची गोनपो की को चीनी पुलिस ने फिर मारा-पीटा 4
- तिब्बती भाषा समर्थक कार्यकर्ता ताशी वांगचुक पर हमला 5
- सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा नौ तिब्बती राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग का स्वागत किया 6
- रणनीतिक योजना का शुभारंभ करने के साथ तिब्बती संसदीय रणनीतिक बैठक संपन्न 7
- जबरन गायब कर दिए गए पीड़ितों के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर डीआईआईआर (सूचना व अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग) का बयान 8
- लंदन प्रतिनिधि को एस्टोनिया के सेटो किंगडम महोत्सव के लिए आमंत्रित किया गया 9
- कोर युप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया ने जी-२० नेताओं से परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत फिर से शुरू कराने की मांग की 10

- वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय ने स्वर्गीय पेमा छेतेन निर्देशित फिल्म थारलो दिखाकर चीन-तिब्बत युवा संवाद की मेजबानी की 11
- उत्तर बंगाल के सालुगाड़ा में तिब्बत समर्थक समूहों (टीएसजी) का सशक्तिकरण और नवीकरण 12
- दार्जिलिंग में भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) के नए चैप्टर का गठन 13
- कलिम्पोंग में तिब्बत समर्थक समूह को मजबूत करने के लिए सीजीटीसी-आई और आईटीसीओ का अभियान 14
- सांसद मिग्युर दोरजी और लोबसांग ग्यात्सो सिथर ने केरल के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की 15
- तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की 16
- तिब्बत पर चीन का दावा गलत, इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास: जनरल नरवणे ने तिब्बती मुक्ति साधनाका समर्थन किया 17

मुद्रक एवं प्रकाशक  
जमयांग दोरजी द्वारा  
नोरबू ग्राफिक्स, 1/6, बेसमेंट  
विक्रम विहार, लाजपत नगर  
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित  
जानकारी के लिए भारत -  
तिब्बत समन्वय केन्द्र की  
वेबसाइट  
www.indiatibet.net  
Email:  
indiatibet7@gmail.  
com



चन्द्रयान-3 की सफलता से तिब्बती समुदाय में खुशी की लहर सम्पूर्ण विश्व, विशेषकर भारत के लिये उत्साहवर्धक है। तिब्बती धर्मगुरु परमपावन दलाईलामा, जो कि तिब्बत के राजप्रमुख भी रहे हैं, ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को इसके लिये हार्दिक बधाई दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक अभिनंदन के पात्र हैं। चन्द्रयान-3 में प्रयुक्त लैंडर विक्रम और चन्द्रमा की सतह से जानकारी जुटाने में सक्षम रोवर प्रज्ञान की सफलता से सम्पूर्ण विश्व का कल्याण होगा। चन्द्रयान-3 से प्राप्त आँकड़े भावी अनुसंधान कार्य में अत्यन्त मददगार सिद्ध होंगे। चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान भेजने वाला भारत विश्व का पहला देश है। यही क्षेत्र सर्वाधिक ठण्ड तथा कई खतरों से भरपूर है। चन्द्रमा की सतह पर उतरने में चन्द्रयान-2 की आंशिक विफलता से स्पष्ट था कि अगला अभियान जरूर सफल होगा। चन्द्रयान-2 जहाँ विफल हुआ था, वह जगह “तिरंगा” है तथा चन्द्रयान-3 जहाँ सफलतापूर्वक उतरा है वह “शिवशक्ति” है। चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित ये दोनों स्थान संपूर्ण विश्व को ऊर्जा देते रहेंगे। प्रज्ञान ने चन्द्रमा की सतह पर अपने भ्रमण मार्ग में हर जगह अशोक स्तम्भ अंकित कर दिये हैं। बौद्ध दर्शन में सम्राट अशोक का योगदान अविस्मरणीय है। उनके ही स्तम्भ से चार सिंहों वाले प्रतीक को हमने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। चन्द्रयान-3 की सफलता पर तिब्बत की निर्वासित सरकार, जो कि तिब्बती जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित है, ने भी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की है और बधाई दी है। गत 23 अगस्त, 2023 को सायं 6 बजकर 4 मिनट पर चन्द्रयान-3 ने चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर अपना अनुसंधान कार्य आरम्भ कर दिया था।

वास्तव में तिब्बती समुदाय भारतीय सुख-दुःख में सदैव साथ है। अभी 15 अगस्त, 2023 को तिब्बत के राजप्रमुख अर्थात् सिक्थोंग पेम्पा छेरिंग ने भारतीय तिरंगा फहराकर भारतीयों को बधाई दी। सभी भारतीय राष्ट्रीय पर्व तिब्बतियों द्वारा पूरे हर्षोल्लास से मनाये जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए पेम्पा छेरिंग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को याद किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तिब्बतियों के संघर्ष के परिणामस्वरूप तिब्बत में भी शोषण का अंधकार नष्ट होगा तथा मुक्ति का सूर्योदय होगा।

इन तथ्यों से साफ है कि भारत एवं तिब्बत की हजारों वर्ष की विश्वसनीय मैत्री भविष्य में भी जारी रहेगी। दलाई लामा और भारत स्थित निर्वासित तिब्बत सरकार का स्पष्ट मत है कि भारत में शरण लेकर तिब्बती अपनी परंपराओं एवं पहचान को सुरक्षित रखे हुए हैं। इनके विकास हेतु उपयुक्त वातावरण यहाँ मिला है। इसी प्रकार भारतीय मानते हैं कि सन् 1959 से भारत में रह रहे दलाई लामा प्राचीन भारतीय संस्कृति, विशेषकर नालंदा परंपरा का विश्वस्तर पर गुणगान कर रहे हैं। इसी परंपरा ने भारत को विश्वगुरु बनाया था। भारतीय एवं तिब्बती आप्त्व हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान के बल पर भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। उस ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता सम्पूर्ण विश्व को है। दलाईलामा के प्रवचनों में इस तथ्य पर सदैव जोर दिया जाता है। उनके अनुसार प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान की परंपरा में मानवीय मूल्यों पर बल है। शांति, अहिंसा, करुणा, मैत्री

तथा सद्भाव मानवीय मूल्य हैं। इनकी आवश्यकता सर्वत्र और सदैव है। दलाई लामा मानते हैं कि मानवीय मूल्य चीन सरकार के लिये और अधिक आवश्यक हैं। दुर्भाग्यवश धर्मविरोधी साम्यवादी चीन सरकार पूर्णतः साम्राज्यवादी-विस्तारवादी-उपनिवेशवादी है। वह स्वतंत्र देश तिब्बत पर सन् 1959 में अवैध नियंत्रण कर चुकी है। मंगोलिया, थाईलैंड, हांगकांग, इस्ट तुर्किस्तान तथा भारत सहित कई अन्य देश उसकी विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। तिब्बती संघर्ष को साथ देने पर चीन सरकार विभिन्न देशों को धमकाती रहती है। सबसे बुरी स्थिति तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों की है। तिब्बत में मीडिया पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में है। तिब्बतियों के मानवाधिकार हनन की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। वहाँ के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी जारी है। तिब्बत की खराब आंतरिक स्थिति की प्रामाणिक जानकारी जुटा पाना काफी कठिन है। चीन सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया तिब्बत में जारी चीनी अत्याचार को छिपाने का कार्य करती है।

तिब्बत में चीनी अत्याचार को रोकने हेतु चीन सरकार पर दबाव बढ़ाना होगा। विश्वजनमत इसी पक्ष में है। दलाईलामा ने तिब्बत के सवाल को अंतरराष्ट्रीय सवाल बना दिया है। निर्वासित तिब्बत सरकार विश्वस्तर पर तिब्बत समस्या के शीघ्र समाधान हेतु सफलतापूर्वक सहयोग एवं समर्थन जुटा रही है। विश्व के सारे देश चीन की चालबाजी समझ चुके हैं। वे उसकी विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने के लिये संगठित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में चीन के अलोकतांत्रिक तथा मानवताविरोधी कुकृत्यों की आलोचना हो रही है। अभी उपयुक्त समय है कि चीन को तिब्बत समस्या शीघ्र निपटाने हेतु बाध्य किया जाये। वह दलाईलामा तथा तिब्बत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के साथ बंद वार्ता पुनः आरम्भ करे। नोबेल पुरस्कारप्राप्त दलाईलामा को विघटनकारी-आतंककारी समझना-कहना वह बंद करे। दलाईलामा एक बौद्ध धर्मगुरु हैं। वे शांति-अहिंसा के पक्षधर हैं। उनके हृदय में क्रूर उपनिवेशवादी चीन सरकार के लिये भी करुणा है। उनकी प्रेरणा से तिब्बती संघर्ष पूर्णतः शांतिपूर्ण और अहिंसक है। चीनी संविधान और राष्ट्रीयता संबंधी कानूनों के अनुसार “तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता” की इनकी मांग मान लेने से चीन को भी लाभ होगा। यह विश्वशांति के लिये भी ठीक होगा।



प्रो० श्यामनाथ मिश्र

पत्रकार एवं अध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग  
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406

E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

## ◆ एसईई लर्निंग मुद्दे पर विचार- विमर्श के लिए प्रतिभागियों के साथ बैठक

dalailama.com, १० अगस्त, २०२३



शेवात्सेल, लेह, लद्दाख, भारत। परम पावन दलाई लामा ने आज १० अगस्त की सुबह लद्दाख में एसईई लर्निंग की कोर टीम के ३० सदस्यों से मुलाकात की। कोर टीम के सदस्यों ने परम पावन को बताया कि एक साल पहले लद्दाख में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके बाद से अब तक उन लोगों ने स्कूलों में ५०० शिक्षकों को सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से प्रशिक्षित किया है। इससे पहले ०९ अगस्त को लेह और कारगिल के १५० शिक्षकों ने इस कार्यक्रम के तहत काम करने के अपने अनुभव पर विचार- विमर्श करने के लिए परम पावन से मुलाकात की थी। उनके प्रवक्ता ने एसईई लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए परम पावन को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर परम पावन ने कहा, 'मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई है। हम तिब्बती जब से भारत में निर्वासन में आए हैं, तब से हमने यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखा है। हमने यहां कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, जिनके मन में धर्म के प्रति बहुत कम आकर्षण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म का पालन करना बहुत मददगार हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के साथ विवाद और झगड़ा करने के लिए बहाने के रूप में धर्म का इस्तेमाल करते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि 'मैंने सक्या, काग्यू और निंगमा परंपराओं के साथ ही गेलुक परंपरा की शिक्षाएं प्राप्त की हैं और मैं उन सभी का पालन करता हूं। लेकिन इस तरह का धर्म हर किसी के पालन करने के लिए नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के आधार पर अपने अंदर प्रेम और करुणा जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित

करने के तरीके खोजें।' परम पावन ने कहा, 'जन्म से ही हमारा पालन-पोषण मां की स्नेहमयी ममता की छांव में होता है। मां के साथ हमारा जुड़ाव कुदरती होता है। इसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं होती है। प्यार और स्नेह का यह अनुभव कुछ मायनों में तो अनुराग और आसक्ति के रंग में रंगा होता है, लेकिन आमतौर पर यह एक प्राकृतिक स्वभाव भर है।' उन्होंने कहा, 'पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के बावजूद ऐसे बहुत लोग हैं जो आज भी लड़ने को उद्धत रहते हैं, भले ही यह लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध का रूप क्यों न ले ले। वे संहारक हथियार विकसित करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग इस तथ्य से बेखबर कि यदि वे परमाणु हथियारों का उपयोग करेंगे तो वेहभी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए, यदि हम शांति स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो पूरी मानवता खत्म हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग किसी धर्म का पालन करते हैं या नहीं। लेकिन हम सब में प्रेम और करुणा का होना बहुत आवश्यक है। नैतिकता का मूल इसी में निहित है। वास्तविकता यह है कि प्रेम और करुणा की कमी के कारण युद्ध लड़े जाते हैं।' उन्होंने कहा, 'मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। लेकिन, मैं प्रेम और करुणा विकसित करने के गुरु को सीखकर उन्हें धर्मनिरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को अपनाने से हमें अपनी माताओं से प्राप्त करुणा और स्नेह को और मजबूत करने और आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। जानवरों को देखो, वे बिना किसी धर्म के हस्तक्षेप के एक-दूसरे के प्रति स्वाभाविक स्नेह का निर्वाह करते हैं। इसी तरह से बच्चे

एक-दूसरे के प्रति नैसर्गिकस्नेह रखते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, राष्ट्र या जाति के हों। बच्चे उन्मुक्त मिलनता का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए वयस्कों के लिए इसका अनुकरण करना बेहतर रहेगा।

उन्होंने कहा, 'हमें विभाजनकारी तत्वों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाए हमें मानवता की एकता की भावना विकसित करने की आवश्यकता है। हमें इस बात के लिए जागरूक होने की ज़रूरत है कि मनुष्य के रूप में हम सब एक समान हैं। हमें पूरी दुनिया में सद्भाव कायम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य के रूप में हम सभी का चेहरा एक ही प्रकार का होता है। यानि, दो आंखें, एक नाक और एक मुंह होता है। यदि हम किसी तीसरी आंख वाले व्यक्ति से मिलें, तो यह सचमुच अजीब होगा।'

परम पावन ने आगे बताया कि 'जब हम तिब्बती लोग निर्वासित होकर यहां आए और अलग-अलग संस्कृति, क्षेत्त्र और मूल के लोगों से मिलेतो पता चला कि हम बिल्कुल उनके जैसे ही थे। हालांकि चीनी कम्युनिस्ट शासन के हमले के कारण हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी आज जब बड़े पैमाने पर चीनी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, हम उनके लिए सहानुभूति और चिंता प्रकट करते हैं। ऐसी आपदाएं जलवायु संकट का लक्षण हैं। मुझे आशा है कि चीनी लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए मैं राहत प्रयासों के लिए दान देने में सफल हो सकूंगा।'

इस अवसर पर बौद्ध साधक होने के तौर पर हम प्रार्थना करते हैं,

सभी प्राणियों को आनंद की प्राप्ति हो

और इस आनंद के कारण

सभी जीव दुखों और

दुख के कारणोंसे मुक्त हों

उन्होंने कहा, हमारे पास भव्य प्राणियों के बारे में केवल अनुमानित अवधारणा है, फिर भी हम कम से कम इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के कल्याण की बात कर सकते हैं।

मेरे मन में बाढ़ से जूझ रहे चीन के लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति है और मुझे आशा है कि वे अपने सामने आने वाली इन चुनौतियों से पार पाने में सक्षम हो जाएंगे। हमारे धर्मग्रंथों में उल्लेख है कि दुनिया अंततः पानी, आग या हवा से नष्ट हो जाएगी और वर्तमान में हमारे सामने उपस्थित ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह के आग का आभास देती है।

उन्होंने याद करते हुए कहा, 'जब मैं पहली बार लद्दाख आया था तो मेरा एक साथी इस बात से व्यथित था कि पहाड़ियां कितनी बंजर हैं। लेकिन पेड़-पौधे लगाने आदि गतिविधियों समेत आपके द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण चीजें अब बदल गई हैं।'

उन्होंने कहा, 'साल के इस समय में धर्मशाला और भारत के मैदानी इलाकों में बारिश के साथ उमस और नमी होती है। जब मैं लद्दाख आता हूं तो मैं इस बात की सराहना करता हूं कि यहां का मौसम शुष्क है और तापमान मध्यम है। मैं उस प्रेम के लिए भी यहां के लोगों के प्रति आभारी हूं जो उनके द्वारा मेरे प्रति दिखाया गया है। धन्यवाद।'

सहानुभूति और करुणा के बीच अंतर पूछे जाने पर परम पावन ने समझाया कि करुणा दूसरों को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए किए जानेवाले

कार्यों को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि दुख तीन प्रकार के होते हैं:- कष्टों से गुजरने का दुख, परिवर्तन का दुख और जनम-मरण के चक्र में व्याप्त दुख। उन्होंने कहा कि जब तक हम कर्म और मोह के चक्कर में फंसकर परिश्रम करते रहेंगे, तब तक हमें कष्ट होता रहेगा। ये वे परिस्थितियां हैं, जिनसे हम मुक्ति पाना चाहते हैं।

उन्होंने बताया कि उन्होंने बोधिचित्त और शून्यता को समझने वाले ज्ञान पर वर्षों तक चिंतन-मनन किया है। परिणामस्वरूप, कर्म संचय के मार्ग का अनुभव प्राप्त कर लिया है और बुद्धत्व के मार्गतक पहुंचने का रास्ता तलाश रहे हैं। देखने के मार्ग से आगे सम्यक्त्व की प्राप्ति और पहला बोधिसत्व मैदान है। वहां से बुद्धत्व की प्राप्ति उसके मार्ग पर बढ़ने और जमीन बनाने की बात है। जब आप देखते हैं कि इस वास्तविकता को हासिल करना संभव है तो इससे इस तरह का आत्मविश्वास आता है कि आपने अपना मानव जीवन सार्थक बना लिया है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कम करने के लिए किए जानेवाले कार्यों के बारे में पूछे जाने पर परम पावन ने उत्तर दिया कि यह अदूरदर्शिता से उत्पन्न हुई एक विकट समस्या है। जो लोग नशीली दवाओं की ओर रुख करते हैं, दरअसल उन्हें अपनी समस्याओं का कोई अन्य समाधान नहीं दिखता है। इसलिए वे समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए नशीली दवाओं की ओर आकर्षित होते हैं। असल में, युवाओं को अपने जीवन को व्यापक संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों और छात्रों को समझाएं और सही काम करने के लिए उनका निर्देशन करना चाहिए। वे बच्चों को बताएं कि इसके बारे में व्यापक और अधिक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाएं।

अंत में, परम पावन से पूछा गया कि एसईई लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे एक शिक्षक को वह क्या सलाह देंगे? इस पर उन्होंने सुझाव दिया कि जब शिक्षा दी जाए तो पूर्व जन्म और अगले जन्म के अस्तित्व जैसे धार्मिक विचारों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां और अभी अधिक तात्कालिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। समस्याओं पर काबू पाने के लिए धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को आधार बनाया जाए।

परम पावन ने एक बात बताई कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में बोधिचित्त के साथ-साथ शून्यता में अंतर्दृष्टि विकसित करने की कोशिश की है। लेकिन वह मानते हैं कि इस तरह का अनुभव हर किसी के लिए नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उनके निजी प्रयास का परिणाम है।

उन्होंने प्रमुख बिंदु के तौर पर बताया कि करुणा के अवतार चैनरेज़िग से प्रार्थना करना आंतरिक विकास का एक साधन है। इसी प्रकार मंजुश्री की अराधना करने से हमें अपने मन से अज्ञानता और अंधेरे को दूर करके अपनी बुद्धि और विवेक को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि भावनाओं के कामकाज के बारे में प्राचीन काल में नालंदा परंपराने जो ज्ञान विकसित किया, बड़ी संख्या में आजकल के वैज्ञानिक इसपर ध्यान दे रहे हैं और उससे सीख रहे हैं।

इसके बाद उन्होंने यहां मिलने आने के लिए प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

## ◆ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का ७७वां स्वतंत्रता दिवस मनाया

tibet.net, १५ अगस्त २०२३



**धर्मशाला।** भारत की आजादी की ७७वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने एक संक्षिप्त समारोह का आयोजन किया। सिक्योंग पेन्या छेरिंग के नेतृत्व में आयोजित समारोह में तिब्बती लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के प्रमुखों-कालोंस, स्वायत्त निकायों के प्रमुखों, सचिवों और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

समारोह की शुरुआत में सिक्योंग ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज- तिरंगे को फहराया और उसके बाद भारत का राष्ट्रगान गाया। समारोह के बाद सिक्योंग ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और इस ऐतिहासिक दिन पर भारत सरकार और भारतीय जनता को बधाई दी।

सिक्योंग ने भारत की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा, 'लंबे समय के ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत अशांति के दौर से गुजरा और फिर १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्त की। आजादी के पिछले ७७ वर्षों में भारत ने आर्थिक, सैन्य और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत प्रगति की है।' हालांकि, इस दौर में उसने कभी दूसरों के प्रति आक्रामक रुख नहीं अपनाया।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं तिब्बत के अंदर और तिब्बत से बाहर रहने वाले तिब्बतियों की ओर से भारतीय लोगों को इस दिन की खुशी मनाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं है। इसकी आप बेहतर कल्पना कर सकते हैं क्योंकि भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रह चुका है। हम भारत सरकार और भारत के लोगों को फिर से बधाई देना चाहते हैं। हम भारत के लोगों से यह भी कहना चाहते हैं कि वे इस आजादी को संजोकर रखें, क्योंकि यह अपने आप नहीं मिली है। आपको लोगों के मौलिक

अधिकारों के लिए काम करना होगा। हम अभी बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आप हर समय हमारा समर्थन करते रहे हैं। हम उस दिन की भी तलाश में हैं जब हम मुक्त वातावरण में तिब्बत वापस जाएंगे।'

तिब्बत वापसी की अपनी उत्कट उम्मीदों के बारे में उन्होंने जोर देकर कहा, 'हम हमेशा आशान्वित रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि यदि कोई आशा नहीं होती तो यह तिब्बत मुद्दा बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। अगर यह आज भी मौजूद है तो इसका कारण यही है कि हमारे मन में आशा बनी हुई है। उम्मीद और आशा के बिना इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आपके उद्देश्य को भी कोई तरजीह नहीं देता है। इसलिए आशा रखना बहुत अधिक अहम बात है। यह बात हर कोई जानता है कि आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत गतिशीलता है। इसलिए आप नहीं जानते कि चीन कब बदल जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तिब्बत की भूमि पर प्रकाश व्याप्त हो जाएगा।'

उन्होंने चीन सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा, 'इस दुनिया में हर कोई स्वतंत्र पैदा हुआ है। इसलिए हम किसी सरकार को यह अधिकार नहीं दे सकते कि वह व्यक्ति के जीवन के हर हिस्से को नियंत्रित करे। इसलिए लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जब तक सरकार लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान नहीं करेगी, कोई भी सत्तारूढ़ सरकार समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर विचार करना होगा। चीन जो भी हथकंडे अपना रहा है, उसकी पूरी खबरें आ रही हैं। वह नियमों में जो भी संशोधन कर रही है या नए नियम आज बना रही हैं, वे अच्छे संकेत नहीं हैं। यह चीनी सरकार की व्याकुलता का संकेत है इसलिए यह अच्छा संकेत नहीं है। इससे लोगों में और अधिक असंतोष पैदा होगा और अंततः ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। इसलिए अगर शांति चाहिए, अगर ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए फायदेमंद हो तो अधिक समझदारी चाहिए। वर्तमान चीनी नेतृत्व के पास ऐसे शासन की ओर बढ़ने की बुद्धि होनी चाहिए जो सरकार और लोगों के साथ ही पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हो।'

## ◆ 'वन चाइना पॉलिसी' का तिब्बतसे कोई लेना-देना नहीं है: सिक्योंग पेन्या छेरिंग

tibet.net ०१ अगस्त, २०२३

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्या छेरिंग ने आज ०१ अगस्त की शाम दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक

कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। इसमें 'एक चीन नीति को हथियार बनाने' पर चर्चा हुई। इसका आयोजन फाउंडेशन फॉर अहिंसक अल्टरनेटिव्स (एफएनवीए) द्वारा कई अनुभवी राजनयिकों और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ किया गया। इस दो दिवसीय सेमिनार के दौरान 'वन चाइना पॉलिसी' के कई पहलुओं पर बात की जाएगी।



अपने संबोधन की शुरुआत में सिक्क्योंग पेन्पा छेरिंग ने तिब्बत के लिए 'वन चाइना पॉलिसी' की अप्रासंगिकता पर प्रकाश डालने के लिए प्रसिद्ध तिब्बती राजनयिक स्वर्गीय ग्यारीलोदो रिनपोछे के एक संस्मरण को उद्धृत किया। दूसरे शब्दों में कहें तो 'वन चाइना पॉलिसी' का संबंध १९७० के दशक में अमेरिकी प्रयासों के नतीजे से है। उस समय अमेरिका द्वारा रिपब्लिक ऑफ चाइना (ताइवान) के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (चीन) के साथ संबंध स्थापित करने के प्रयास चल रहे थे। इसका तिब्बत के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं थी। उद्धरण में लिखा है, 'फिर भी पीआरसी सरकार तिब्बत में 'वन चाइना पॉलिसी' को लागू करने का सख्ती से प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में चीनने कई सरकारों को यह कह कर न केवल 'वन चाइना पॉलिसी' पर विश्वास करने के लिए गुमराह किया है कि यह तिब्बत पर लागू होता है, बल्कि उसने उन सरकारों के अधिकारियों को निर्वासित तिब्बती नेताओं के साथ ही परमपावन दलाई लामा से भी संपर्क करने या बातचीत करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

सिक्क्योंग पेन्पा छेरिंग ने तिब्बत और चीन के साथ भारत सरकार के संपर्कों के बारे में संक्षेप में बात करते हुए कहा, 'जब आप तिब्बत के बारे में बात करते हैं तो आपको १९४५ से ५१ और ५४ तक बात करनी होगी जब तिब्बत आजाद था।' उन्होंने दोहराया, 'वन चाइना पॉलिसी या एक चीन नीति का तिब्बत के लिए और तिब्बत से कोई लेना-देना नहीं है। आपको इसे बिल्कुल अलग चश्मे या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखना होगा।'

सिक्क्योंग ने आगे तिब्बत और चीन के बीच १७ सूलिय समझौते पर प्रकाश डाला, जिस पर तिब्बती राजनयिकों को चीन के दबाव में हस्ताक्षर करना पड़ा था। बाद में परम पावन १४वें दलाई लामा के नेतृत्व वाली तिब्बती सरकार द्वारा समझौते का पालन करने के लिए प्रयास किए गए, जिसे चीन ने अंततः नजरअंदाज कर दिया। इसके कारण उस समझौते की पवित्रता नष्ट हो गई और परिणामस्वरूप परम पावन दलाई लामा के साथ हज़ारों तिब्बतियों को निर्वासन में पलायन करना पड़ा था।

सिक्क्योंग से पहले पूर्व भारतीय राजदूत लखन लाल मेहरोला ने भी कार्यक्रम के उद्घाटन सत्रको संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'चीन के उदय ने एक नई स्थिति पैदा कर दी है जिसमें स्थापित वैश्विक समीकरण टूट रहे हैं, जिससे पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चुनौतियां पैदा हो रही हैं।' विशेष रूप से, उन्होंने अमेरिका और भारत के साथ चीन के संबंधों और उसमें लगातार हो रहे बदलावों के बारे में बात की।

## ◆ अपने कैदी भाई से मिलने पहुंची गोनपो की को चीनी पुलिस ने फिर मारा-पीटा

tibet.net, ०२ अगस्त, २०२३



**धर्मशाला।** तिब्बत से आई नवीनतम वीडियो क्लिप में जेल में बंद प्रसिद्ध तिब्बती उद्यमी दोर्जी ताशी की बड़ी बहन गोनपो की ने एक बड़ा खुलासा किया है। गोनपो का कहना है कि कल ०१ अगस्त को द्रापची जेल के पास चीनी पुलिस के एक समूह ने उनको मारा-पीटा। वीडियो में गोनपो की कहती हैं, '०१ अगस्त को मैंने द्रापची जेल के पास के थाने से संपर्क किया और देश के संविधान और कानून के प्रावधानों के तहत अपने भाई से मिलने के लिए अधिकारियों से अनुमति मांगी। चूंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने अधिकारियों के सामने साष्टांग दंडवत किया और अनुरोध किया कि चीनी संविधान के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। अधिकारियों ने मुझे बर्बरता से ज़मीन पर घसीटा और साष्टांग दंडवत करने के कारण मुझ पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अपनी बांहों और कोहनियों पर घसीटने के कारण छिलने के निशान दिखाते हुए वह कहती हैं, 'ये जेल पुलिस के हाथों मुझे पीटे जाने और घसीटे जाने के सबूत हैं। चूंकि मैंने अपने कैदी भाई से मिलने का अनुरोध किया था, इसलिए लगभग चार से पांच पुलिसवालों ने मुझे जानवरों की तरह घसीटा। भाई से मिलने के लिए मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था।'

एक महीने पहले १३ जुलाई को गोनपो की ने एक अन्य वीडियो बयान में अपने भाई दोर्जीताशी की कुशलता को लेकर गहरी चिंता जताई थी और चीनी कानून और संविधान के अनुसार उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी।

दोर्जीताशी चीनी जेल में १५ वर्षों से अधिक समय से बंद हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोर्जीताशी के परिवार के सदस्यों की चिंताएं उन पर होने वाली यातनाओं और पिटाई के कारण उनके गिरते स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जा रही हैं। मामले की निष्पक्ष सुनवाई और समीक्षा कराने के कई अनुरोधों के बावजूद वह अभी भी जेल में बंद हैं। जेल में उनसे मिलने से उनके परिवार को मनाकर दिया गया है और उच्च अधिकारियों से की गई उनकी अपील बेकार साबित हुई है। उन पर निर्वासित तिब्बतियों को दान देने और तिब्बत में तिब्बती प्रदर्शनकारियों को धन मुहैया कराने का संदेह जताया गया था। इसी आरोप के संदेह में दोर्जीताशी को १० जुलाई २००८ को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद १७ मई २०१० को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

## ◆ तिब्बती भाषा समर्थक कार्यकर्ता ताशी वांगचुक पर हमला

freetibet.org, २१ अगस्त, २०२३

भाषा समर्थक कार्यकर्ता और पूर्व राजनीतिक कैदी ताशी वांगचुक पर शनिवार १९ अगस्त को कुछ अज्ञात और नकाबपोश लोगों के समूह ने हमला कर दिया था।

‘फ्री तिब्बत’ के शोध सहयोगी संस्था ‘तिब्बत वॉच’ ने खुलासा किया है कि स्कूलों में चीनी भाषा लागू करने के लिए तिब्बती भाषा में पढ़ाई को खत्म करने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ताशी वांगचुक ने १९ अगस्त की शाम को पूर्वी तिब्बत में डार्लक काउंटी की यात्रा की थी। उन्होंने डार्लक काउंटी नेशनलिटी मिडिल स्कूल के पास एक वीडियो फिल्माया और उसे चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डॉयिन पर पोस्ट किया। इसके बाद वे अपने अपने होटल चले गए।

उसी रात लगभग ०८ बजे ताशी वांगचुक के होटल के कमरे का दरवाजा जबरदस्ती तोड़ा गया और नकाबपोश लोगों के एक समूह ने उन्हें लगभग १० मिनट तक लात-घुसों से पीटा। उनका मानना है कि स्कूल से होटल तक उनका पीछा किया गया था।

ताशी वांगचुक हमलावरों के सामने गिड़गिड़ाते रहे और उन्हें छोड़ने की विनती करते रहे। बाद में उन्होंने होटल मालिक से पुलिस बुलाने के लिए आग्रह किया। पुलिस रात करीब ०९ बजे उनके होटल के कमरे में पहुंची और उन्हें पूछताछ के लिए थानेले गई, जहां ताशी वांगचुक रात करीब ११:३० बजे तक रहे। इस दौरान पुलिस ने ताशी वांगचुक को अपने फोन से उस दिन ली गई तस्वीरें और वीडियो को मिटाने के लिए मजबूर किया।

इसके बाद उनके रुकने वाले होटल ने उन्हें वहां कमरा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कई अन्य होटलों ने भी उन्हें कमरा देने से मना कर दिया। इसके बाद वह डार्लक काउंटी अस्पताल गए और डॉक्टर से अपने सिर की जांच करने के लिए कहा। डॉक्टर ने जवाब दिया कि सीटी स्कैनर खराब है। ताशी वांगचुक ने पूरी रात अस्पताल की पहली मंजिल पर एक स्टूल पर बैठकर बिताई। इस दौरान उन्होंने दिन भर की घटनाओं का एक विस्तृत विवरण तैयार किया। इसमें उन्होंने अपनी पिटाई का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने इस रिपोर्ट में ‘अपराधीगिरोह और सरकारी अधिकारियों द्वारा कानून तोड़ने वाले अवैध कृत्य करने और एक-दूसरेको बचाने’ वालों के रूप में संदर्भित किया।

ताशी वांगचुक पूर्वी तिब्बत के युलशुल (चीनी: युशु) प्रीफेक्चर में क्येगुडो से है। स्थानीय स्कूलों में तिब्बती भाषा की कक्षाएं बंद होने के बाद स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के अपने प्रयासों को लेकर २०१५ में न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करने के बाद वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि में आए। इसमें उन्होंने तिब्बत की भाषा और संस्कृति के भविष्य को लेकर भी आशंका व्यक्त की। ताशी वांगचुक ने आरोप लगाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख और वीडियो वृत्तचित्र के लिए ही उन्हें चिह्नित किया गया और हमला किया गया। यह लेख और वीडियो नवंबर २०१५ में प्रकाशित- प्रसारित किया गया था।

जनवरी-२०१६ में ताशी वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा गया और प्रताड़ित किया गया। दो साल बिना मुकदमों के हिरासत में रखे जाने के बाद उन्हें ‘अलगाववाद भड़काने’ का दोषी पाया गया और पांच साल जेल की सजा सुनाई गई। उनकी हिरासत और कारावास की सजा के खिलाफ तिब्बती समूहों ने दुनिया भर में अभियान चलाया और ताशी वांगचुक को रिहा करने की मांग की।

ताशी वांगचुक ने जनवरी-२०२१ में जेल से रिहा होने के बाद भी तिब्बत में अधिकारियों से चीनी संविधान का सम्मान करने की वकालत करना जारी रखा है, जिसमें तिब्बती सहित अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है।



जनवरी-२०२२ में ताशी वांगचुक ने तिब्बती भाषा के संरक्षण के लिए ज्येकुंडो में स्थानीय सरकारी कार्यालयों से संपर्क किया। इसके चलते उन्हें युशू के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने चीन के कब्जे वाले तिब्बत के अन्य स्कूलों की भी यात्राएं कीं और तिब्बती भाषा की जगह चीनी भाषा में शिक्षा देने वाली पाठ्य-पुस्तकें एकत्र की हैं।

एक ओर जहां ताशी वांगचुक तिब्बती भाषा के पक्ष में शांतिपूर्ण ढंग से अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीनी कब्जे वाले तिब्बत में अधिकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज में तिब्बती भाषा को हाशिए पर रखने या यहां तक कि खत्म करने की नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों में तिब्बती भाषा के स्कूलों को बंद करना और चीनी सरकार की आवासीय स्कूल नीति को लागू करना शामिल है। इन आवासीय स्कूलों में ०४ से १८ वर्ष की आयु वर्ग के लगभग दस लाख तिब्बती बच्चों को जबरन रखा गया है। इस माहौल में बच्चों की अपने परिवारों से बहुत कम मिलने दिया जाता है और उन्हें ऐसे शैक्षणिक माहौल में रखा जाता है जहां तिब्बतियों की अपनी भाषा और इतिहास के खिलाफ चीनी भाषा और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अनुमोदित इतिहास को बढ़ावा दिया जाता है। इस नीति की संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी समिति ने आलोचना की है। इस विश्व संस्था ने मार्च २०२३ में चीन से आवासीय विद्यालय प्रणाली को समाप्त करने का आग्रह किया था।





## ◆ सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा नौ तिब्बती राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग का स्वागत किया

tibet.net, ११ अगस्त, २०२३

धर्मशाला। संयुक्त राष्ट्र के तीन स्वतंत्र विशेषज्ञों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की सरकार से उन नौ तिब्बती पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बारे में ठोस और सही जानकारी प्रदान करने की मांग की, जिन्हें हिरासत में लिया गया था और लंबी जेल की सजा सुनाई गई थी। विशेषज्ञों ने यह भी मांग की कि अगर चीन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के प्रति गंभीर है तो उनकी तत्काल रिहाई की जाए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टियर सुश्री मैरी लॉलर, शांतिपूर्ण सभा और एसोसिएशन की स्वतंत्रता पर विशेष रिपोर्टियर श्री क्लेमेंट न्यालेत्सोसीवोउले और सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण का लाभ लेने से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों के मुद्दे पर विशेष रिपोर्टियर श्री डेविड बॉयड ने १० अगस्त २०२३ को जारी एक संयुक्त बयान जारी किया। संयुक्त बयान में इन तीनों दूतों ने तिब्बती मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हिरासत और सजा को लेकर पीआरसी द्वारा जानकारी नहीं देने और इन मुद्दों की अनदेखी करने पर चिंता व्यक्त की। उनका मानना है कि यह अनदेखी दुनिया को इन मुद्दों से नजर हटाने को लेकर जान-बूझकर किया गया प्रयास है। इसके अलावा विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई कि इन कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी से उनके परिवारों को अंधेरे में रखा गया है।

चीन में न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता से इनकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने उन तिब्बतियों की हिरासत, मुकदमे या सजा की परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट रूपरेखा प्रदान नहीं की है। इनका कहना है कि चीन में पक्षपातपूर्ण न्यायिक प्रणाली की विशेषता अक्सर अस्पष्ट और भेदभावपूर्ण होना और आरोपों पर बंद दरवाजों के पीछे संदिग्ध रूप से सुनवाई करना है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां उनके पास 'पर्याप्त' जानकारी है, इन तिब्बती पर्यावरण कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया है और सात से ११ साल की जेल की सजा सुनाई गई है। विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं हैं कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हिरासत के दौरान कानूनी सलाह प्रदान की गई है या उन्हें जेल में रहते समय चिकित्सा देखभाल की गई।

ज्ञातव्य है कि पवित्र पर्वतों पर अवैध खनन गतिविधियों का विरोध करने और अमदों के तिब्बती क्षेत्रों और खाम प्रांत में लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार का खुलासा करने के कारण नौ पर्यावरण मानवाधिकार कार्यकर्ताओं- अन्या सेंगद्रा, दोरजी डैक्टल, केलसांग चोकलांग, ढोंगये, रिनचेन नामडोल, छुल्ट्रिम गोन्पो, जांगचुप न्गोदुप, सोगरूअभु और नेमेसी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। खाम प्रांत अब चीन के किंगई और सिचुआन प्रांत और तथाकथित तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है।

अपने बयान में विशेषज्ञों ने अनुरोध किया है कि पीआरसी सरकार इन छह मानवाधिकार

कार्यकर्ताओं की सजा की अवधि, उनके ठिकाने और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए। विशेषज्ञों ने अनुरोध किया है कि पीआरसी सरकार उन्हें क्यों और कहां हिरासत में रखा जा रहा है और उनके स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में विवरण प्रदान करें और उनके परिवारों को उनसे मिलने की अनुमति दें। विशेषज्ञों ने जोर देते हुए बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए चीन की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया गया है। साथ ही विडंबना यह भी है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के खिलाफ लड़ाई में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को दंडित किया जा रहा है। उन्होंने तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की वकालत करने के लिए गैरकानूनी रूप से कैद किए गए सभी नौ तिब्बती कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के कालोन नोरज़िन डोल्मा ने संयुक्त बयान का स्वागत किया और पिछले दशक में चीन द्वारा तिब्बती मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी तरीके से चुप कराने की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को धन्यवाद दिया। कालोन ने चीन से उन सभी तिब्बती राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का भी आग्रह किया, जिन्हें केवल तिब्बती संस्कृति, भाषा और पर्यावरण को चीनी अधिकारियों द्वारा नष्ट किए जाने से बचाने के अपने बुनियादी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कैद किया गया है।

## ◆ रणनीतिक योजना का शुभारंभ करने के साथ तिब्बती संसदीय रणनीतिक बैठक संपन्न

tibet.net, १२ अगस्त, २०२३

दिल्ली। निर्वासित तिब्बती संसद (टीपीआईई) की पांच दिवसीय रणनीतिक बैठक दिल्ली में ०६ से ११ अगस्त २०२३ तक आयोजित की गई। यह बैठक १७वीं निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेनपोसोनम तेनफेल, उपाध्यक्ष डोल्मा छेरिंग तेखांग और निर्वासित

तिब्बती सांसदों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। टीपीआईई की तीसरी रणनीतिक बैठक सांसदों के बीच पक्षधरता के उन्नत कौशल और एक नई भावना के साथ अंग्रेजी और तिब्बती भाषाओं में टीपीआईई रणनीतिक योजना २०२३-२०२६ दस्तावेज के लॉच के साथ संपन्न हुई।



दस्तावेजों के लॉच के दौरान निर्वासित संसद की उपाध्यक्ष ने टीपीआईई रणनीतिक योजना २०२३-२०२६ के महत्व और विशेष रूप से इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के बारे में बताया। निर्वासित संसद के अध्यक्ष ने बताया कि दस्तावेज को शुरू में प्रत्येक सांसद को ईमेल से भेजा गया और फिर स्थायी समिति की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया। तिब्बती सांसदों ने अपने सामूहिक प्रयास के बारे में विचार व्यक्त किए और रणनीतिक योजना में सूचीबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी सिफारिशें बताईं।

टीपीआईई रणनीतिक योजना २०२३-२०२६ मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांतों, रणनीतिक लक्ष्यों और कार्य योजनाओं पर केंद्रित है। इस योजना में टीपीआईई के लिए अगले चार वर्षों में काम करने के लिए छह रणनीतिक लक्ष्य और सूचीबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्य योजनाएं शामिल हैं।

तिब्बती सांसदों ने उसी दिन भारतीय संसद की लोकसभा के सदस्य श्री राजेंद्र अग्रवाल और राज्यसभा के सदस्य डॉ. अमीयाज्ञानिक के साथ विचार आदान-प्रदान सत्र का भी आयोजन किया।

अंतिम दिन एक समापन सत्र आयोजित किया गया, जहां निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि पांच दिवसीय बैठक के दौरान तिब्बती सांसदों और भारतीय गणमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों के बीच हुई चर्चा टीपीआईई के भविष्य के कार्यों का मार्गदर्शन करेगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक ने तिब्बती सांसदों को भारतीय संसद के सदस्यों के साथ बातचीत करने और इसके दोनों सदनों के सदस्यों को अपना संदेश देने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया, जिसमें तिब्बत के लिए सर्वदलीय भारतीय संसदीय फोरम फॉर तिब्बत (एपीआईपीएफटी) के संयोजक श्री सुजीत कुमार भी शामिल थे।

निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष ने रणनीतिक बैठक के दौरान आवंटित समितियों में चर्चा में सक्रिय भागीदारी के लिए भाग लेने वाले तिब्बती सांसदों की सराहना की और उनके प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने आगे कहा कि बैठक अपेक्षाओं से अधिक सफल रही, लेकिन इसमें निहित लक्ष्यों को पूरा करने की मुख्य जिम्मेदारी सांसदों की है।

बैठक के पहले दिन राज्यसभा सदस्य और तिब्बत के लिए सर्वदलीय भारतीय संसदीय फोरम फॉर तिब्बत (एपीआईपीएफटी) के अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार के साथ विचार-विमर्श का सत्र हुआ, जहां उन्होंने चीन-तिब्बत संघर्ष के मुद्दे को लेकर भारत की तिब्बत नीति, भारतीय संसद, चीन-भारत संबंध और तिब्बत आउटरीच अभियानों को ऊपर उठाने के तरीकों पर चर्चा की। पहले दिन के कार्यक्रम में नई दिल्ली के

फाउंडेशन फॉर नॉन-वायलेंट अल्टरनेटिव्स (एफएनवीए) के ट्रस्टी ओपी टंडन और रेबन बनर्जी द्वारा प्रस्तुत 'भारत की तिब्बत नीति-२०२२ को पुनर्निर्धारित करना' और ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रतिष्ठित फेलो डॉ. मनोज जोशी द्वारा प्रस्तुत 'तिब्बत पर चीन के २०२१ के श्वेत पत्र के भारत की चीन रणनीति के संदर्भ में निहितार्थ' पर बातचीत भी शामिल थी।

निर्वासित तिब्बती संसद की रणनीतिक बैठक के दूसरे दिन इंडिया वॉटर फाउंडेशन के अध्यक्ष और विश्व जल परिषद के गवर्नर डॉ. अरविंद कुमार द्वारा 'दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के खतरे' पर व्याख्यान दिया गया। पहले दिन जिन विषयों पर चर्चा हुई, उन पर तिब्बती सांसदों के बीच मंथन भी हुआ। तिब्बत के लिए सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच के संयोजक सांसद श्री सुजीत कुमार ने उसी दिन निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदस्यों के सम्मान में हाई टी पार्टी की मेजबानी की। हाई टी में राज्यसभा सदस्य डॉ. अशोक बाजपेयी और राज्यसभा सांसद श्री अनिल हेगड़े भी शामिल हुए। चाय पर भारतीय और तिब्बती सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।

टीपीआईई रणनीतिक बैठक के तीसरे दिन 'द हिंदू' अखबार की कूटनीतिक संपादक सुहासिनी हैदर द्वारा पेश 'भारत की तिब्बत नीति के संबंध में भारत की विदेश नीति में देखने लायक पांच रुझान' और भारत के परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर प्रधानमंत्री के पूर्व दूत, भारत के पूर्व राजदूत और पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन द्वारा पेश 'भारत-चीन संबंध' विषय पर विचार-विमर्श किया गया। बाद में शाम को तिब्बती सांसदों ने राज्यसभा सदस्य श्री ए.डी. सिंह के साथ एक सार्थक संवाद-सत्र भी किया।

रणनीतिक बैठक के चौथे दिन तिब्बती सांसदों ने राज्यसभा सदस्य श्री अनिल हेगड़े और राज्यसभा सदस्य डॉ. अशोक बाजपेयी के साथ एक बहुत ही सार्थक विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इनके साथ भाजपा नेता श्री राजेश दीक्षित भी थे। बैठक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व विकास और संघर्ष समाधान के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मितिका एनरिचिंग लाइफस्पेस के सह-संस्थापक और निदेशक दुर्बा घोष ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जटिलताओं पर बात की, जबकि मितिका की जया अय्यर ने व्यक्तित्व विकास पर बात की। घोष और अय्यर ने 'संघर्ष समाधान-शांति निर्माण' पहल पर भी बात की।

यह निर्वासित तिब्बती संसद की तीसरी रणनीतिक बैठक है। पिछली दो बैठकें क्रमशः सितंबर और नवंबर-२०२२ में हरियाणा और धर्मशाला में आयोजित की गई थीं।

## ◆ जबरन गायब कर दिए गए पीड़ितों के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर डीआईआईआर (सूचना व अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग) का बयान

tibet.net, ३० अगस्त, २०२३

**धर्मशाला।** जबरन गायब कर दिए गए पीड़ितों के ४०वें अंतरराष्ट्रीयदिवस के अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) उन सभी तिब्बतियों को याद करता है जिन्हें तिब्बत के अंदर गायब होने के लिए मजबूर किया गया है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) से जोरदार आग्रह करता है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

किसी भी व्यक्ति का जबरन गायब होना मानवता के खिलाफ एक अपराध है। चाहे वह अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो। साथ ही इसमें जीवन का अधिकार, यातना से मुक्त होने का अधिकार, मनमानी हिरासत से मुक्त होने का अधिकार, कानून के समक्ष मान्यता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित अधिकारों की सीमाओं का उल्लंघन भी शामिल है।

प्रोटेक्ट ऑल पर्संस फ्रॉम इंफोर्स्ड डिसैपियेंस (सभी व्यक्तियों को जबरन गायब होने से बचाने के लिए) पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के पहले अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था यह निर्धारित करता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को जबरन गायब नहीं किया जाएगा। और न ही इसे उचित ठहराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सदस्यों में से एक चीन को चार्टर के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में संयुक्त राष्ट्र को सभी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। इसमें संबंधित उपकरणों और सम्मेलनों के अनुसार कार्य करना भी शामिल है, भले ही उन्होंने उन पर हस्ताक्षर किए हों और उनकी पुष्टि की हो।

तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद तिब्बतियों को अक्सर लंबे समय तक के लिए हिरासत में रखा गया है। साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों की कुशलता और उनके ठिकाने के बारे में उनके परिवार और रिश्तेदारों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे गंभीर चिंता पैदा हो रही है। इसके अलावा, हिरासत में रहने के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को अक्सर गंभीर रूप से प्रताड़ित किया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा होती हैं और अंततः खराब स्वास्थ्य स्थितियों के कारण कैदी की मृत्यु हो जाती है।

दुनिया में सबसे उल्लेखनीय जबरन गायब किए जाने के मामलों में से एक तिब्बत के ११वें पंचेन लामा जेछुन तेनजिन गेधुन येशी ट्रिनले फंटसोक पाल सांगपो का है। इनका अपहरण उस समय कर लिया गया था, जब वह केवल छह साल के थे। चीनी अधिकारियों ने उन्हें और उनके परिवार को तब से लोगों की आंखों से ओझल कर रखा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा पीआरसी से उनकी रिहाई की बार-बार की अपील और मांग के बावजूद २८ साल बाद भी पंचेन लामा की कुशलता, उनके ठिकाने के बारे में संदेह है। वह जीवित भी हैं या नहीं, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है।

पीआरसी की जबरन गायब करने के तरीके का दोहरा असर होता है। इसमें तिब्बती पीड़ितों के दिमाग और शरीर के साथ-साथ उनके परिवारों और रिश्तेदारों में भी आतंक पैदा किया



जाता है और साथ ही गैर कानूनी गिरफ्तारी और हिरासत को उचित ठहराने के लिए कैदियों को यातनाएं देकर उनसे जबरन बयान दिलवाया जाता है। अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए अधिकांश तिब्बतियों-लामा, मठवासी, समुदाय के नेता, लेखक और कवि, बुद्धिजीवी, गायक, खानाबदोश और छात्र - को कथित 'अपराधों' की सुनवाई के लिए चीनी अदालतों में लाए जाने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा महीनों तक गायब रखा जाता है।

डीआईआईआर ने १० अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के तीन स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा पीआरसी सरकार से नौ तिब्बती पर्यावरण मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए किए गए आह्वान की पुष्टि की और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था और लंबी जेल की सजा सुनाई गई थी।

जहां तक चीनी आपराधिक प्रक्रिया कानून में जबरन गायब होने के बारे में प्रावधान है, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य ऐसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से बदलना अनिवार्य है, जो 'खतरनाक सरकारी सुरक्षा' और 'आतंकवाद' के संदिग्धों के लिए हैं। इसके साथ ही गायब किए गए तिब्बती राजनीतिक कैदियों को चीन द्वारा तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और उनके परिवारों को उनके ठिकाने और कारावास की शर्तों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

## ◆ लंदन प्रतिनिधि को एस्टोनिया के सेटो किंगडम महोत्सव के लिए आमंत्रित किया गया

tibet.net, ११ अगस्त, २०२३

लंदन। लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि सोनम फ्रैसी ने पिछले दौरा किया।

साल जनवरी में अपनी पिछली यात्रा के दौरान तिब्बत के लिए पक्षधरता स्थापित करने के लिए ०४ से ०९ अगस्त २०२३ तक बाल्टिक देशों का

इस बार उनकी एस्टोनिया की यात्रा सेटो साम्राज्य के आधिकारिक निमंत्रण पर थी, जिसके दौरान सेटो हाउस सामुदायिक केंद्र ने प्रतिनिधि



सोनम फ्रैसी की यात्रा के सम्मान में तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिब्बत से संबंधित किताबें सेटो सामुदायिक पुस्तकालय को दान कर दी गईं। प्रतिनिधि फ्रैसी अपने साथ परम पावन दलाई लामा का एस्टोनिया के राष्ट्रपति रिइगिकोगु के नाम पत्र ले गए थे और उनकी मुलाकात को सबसे बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्र पोस्टिमीज़ में कवर किया गया।

प्रतिनिधि सोनम फ्रैसी ने सेटो किंगडम में सेटो किंगडम महोत्सव में प्रस्तुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की।

प्रतिनिधि ने तिब्बत की मौजूदा स्थिति और चीन द्वारा तिब्बती संस्कृति

और पहचान को जान-बूझकर नष्ट करने के प्रयास पर बात की। सेटो किंगडम के प्रति तिब्बत के लोगों के सम्मान के प्रतीक के तौर पर प्रतिनिधि ने तिब्बत के राष्ट्रीय ध्वज को दोनों देशों के लोगों और संस्कृति के बीच मजबूतमिलता के रूप में प्रस्तुत किया।

अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान प्रतिनिधि फ्रैसी ने सेटो साम्राज्य के नेताओं और परिषद सदस्यों, धार्मिक प्रमुखों, संसद सदस्यों, तिब्बत समर्थकों के साथ ही एस्टोनियाई सरकारी अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उन्हें तिब्बत के इतिहास, वर्तमान और तिब्बत के शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी दी और इसके लिए समर्थन जुटाया।

प्रतिनिधि फ्रैसी ने लैटेविया में हाल के आम चुनावों के बाद तिब्बत के लिए नवगठित संसदीय मैत्री समूह से मिलने के लिए वहां का दौरा किया और तिब्बत के वर्तमान स्थिति पर सदस्यों को ताजा जानकारी दी। इसमें सांसद गिर्ट्स लापिन्स भी शामिल हैं जो संसदीय समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और स्थानीय तिब्बत समर्थकों से भी मुलाकात की।

## ◆ कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन काँज- इंडिया ने जी-२० नेताओं से परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत फिर से शुरू कराने की मांग की

tibet.net, २५ अगस्त २०२३

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन काँज- इंडिया (सीजीटीसी-आई) ने २४ अगस्त-२०२३ को नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजीटीसी-आई के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर.के. खिरमे के साथराष्ट्रीय सह-संयोजकों-श्री सुरेंद्र कुमार एवं श्री अरविंद निकोसे और क्षेत्रीय संयोजक श्री पंकज गोयल ने भाग लिया।

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन काँज- इंडिया (सीजीटीसी-आई) भारत में सक्रिय विभिन्न तिब्बत समर्थक समूहों (टीएसजी) का सर्वोच्च निकाय है। यह देश में तिब्बती मुद्दे का समर्थन करने वाले भारतीयों का छतरी संगठन है, जिसका काम तिब्बती मुद्दे के समर्थन में समन्वय, निर्देशन, योजना निर्माण और गतिविधियों को शुरू करना है।

### प्रेस विज्ञप्ति:

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन काँज- इंडिया (सीजीटीसी-आई) ने चीनी सरकार को तिब्बत सरकार में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए दोषी बताने तथा परम पवन दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए : जी- २० के नेताओं पर दबाव डालने के लिए अनुरोध।

नई दिल्ली, (२४ अगस्त, २०२३)। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन काँज- इंडिया (सीजीटीसी-आई) भारत में सभी तिब्बत समर्थक समूहों (टीएसजी) का सर्वोच्च संगठन है। इसका कार्य तिब्बती मुद्दे के समर्थन के लिए समन्वय, निर्देशन, योजना और गतिविधियों को संचालित करना है।

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन काँज - इंडिया (सीजीटीसी-आई) ने जी-२० नेताओं से चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। विशेष रूप से उन रिपोर्टों पर ध्यान देने की अपील की गई है जिसमें दस लाख से अधिक



तिब्बती बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर दिया गया है और तिब्बत में अनिवार्य आवासीय स्कूल प्रणाली में डाल दिया गया है। इस स्कूल नीति का उद्देश्य तिब्बत की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई रूप को नष्ट करना है। ये आवासीय स्कूल चीनी कम्युनिस्ट विचारधाराओं और उनके द्वारा गढ़ी जा रही कहानियों के साथ राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, जो अभी चीन के अनधिकृत और बलात कब्जे में है।

तिब्बत अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत की तरह ही लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है और चीनी सरकार द्वारा गंभीर मानवाधिकारों के हनन, सांस्कृतिक दमन और धार्मिक भेदभाव की रिपोर्टों के साथ यह एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तिब्बतन का वर्तमान चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है, जिस पर तत्काल विश्व के देशों को ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन काँज - इंडिया (सीजीटीसी-आई) का मानना

है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले जी-२० नेताओं को इन गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने और समाधान करने की नैतिक जिम्मेदारी है।

अपने अधिकारों और पहचान के लिए तिब्बती लोगों के संघर्ष को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में नागरिकों को गायब कर देने, मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और सांस्कृतिक रूप से अपना वर्चस्व कायम करने की घटनाएँ बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सीजीटीसी-आई जी-२० नेताओं से इन अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होने और सभी के लिए मानवाधिकार और सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखने का मांग करता है।

ऐसे समय में, जब जी-२० देशों के नेता ०९ से १० सितंबर को नई दिल्ली में आगामी शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हो रहे हैं, सीजीटीसी-आई उनसे निम्नलिखित मांगों को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है:-  
कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़-इंडिया (सीजीटीसी-आई) मांग करता है:

### १. मानवाधिकार उल्लंघन की तत्काल जवाबदेही :

- जी-२० नेताओं को तिब्बत में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जी-२०के सदस्य चीन को उत्तरदायी ठहराया जाए, जिसमें अनिवार्य आवासीय स्कूलों के माध्यम से तिब्बती बच्चों को निशाना बनाया जाना भी शामिल हो।
- मानवाधिकारों के हनन की रिपोर्टों में पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग की जाए।

विश्व के राजनयिकों, मिडिया, बुद्धिजीवियों और आमजनता को तिब्बत में प्रवेश की अनुमति हो।

### २. परम पावन १४वें दलाई लामा का पुनर्जन्म

इसकी घोषणा की जाए कि परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म के संबंध में निर्णयों पर अंतिम अधिकार निर्विवाद रूप से और पूरी तरह से स्वयं परम पावन दलाई लामा और संबंधित अधिकारियों के पास है।

जी- २० के नेतागण यह ऐलान करें कि कोई भी राष्ट्र, सरकार, जिसमें चीनी सरकार, संस्था या कोई भी व्यक्ति शामिल है, परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने का अधिकार नहीं है।

### ३. तिब्बती बच्चों के अधिकारों का संरक्षण:

अनिवार्य आवासीय स्कूलों के माध्यम से जबरन नस्लीय तौर पर विलय कर लिये गए दस लाख से अधिक तिब्बती बच्चों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की कड़ी निंदा करे।

जी-२० सम्मेलन की ओर से चीनी सरकार से उन सभी नीतियों को तुरंत बंद करने का आग्रह किया जाए, जो तिब्बती बच्चों के अद्वितीय सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को बनाए रखने के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। तिब्बत में चीनी अधिकारियों द्वारा लागू की गई आवासीय विद्यालय प्रणाली ने तिब्बत में तिब्बती बच्चों को अकथनीय पीड़ा और अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग कर दिया जाता है और उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को मिटाने के उद्देश्य से कार्यवाही चलाई जाती है।

### ४. परम पावन १४वें दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की बहाली:

जी-२० नेताओं से मांग है की चीन की सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाये की तिब्बत की समस्या के अंतिम समाधान के लिए परम पवन दलाई लामा के प्रतिनिधि से पुन संवाद शुरू कर तिब्बत का शांतिपूर्ण, रचनात्मक और परस्परिक स्वीकार्य समाधान का मार्ग प्रशस्त करे।

५. जी-२० शिखर सम्मेलन के एजेंडे में तिब्बत को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया जाए:

जी-२० नेताओं से मांग करते हैं कि तिब्बत को अतिमहत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में सम्मेलन के विचारथ शामिल किया जाये। सबों के लिए मानवाधिकार, उत्पीड़ित समुदाय, सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं।

६: कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़ - भारत मांग करता है की तिब्बत समास्या की शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय और महत्वपूर्ण बिन्दू के रूप में विचार के लिए सम्मिलित किया जाये।

७: कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़ – भारत: मांग करता है कि तिब्बत की समस्या की अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए विचार करे ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तिब्बत में न्याय, मानवाधिकार और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त सके

## ◆ वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय ने स्वर्गीय पेमा छेतेन निर्देशित फिल्म थारलो दिखाकर

### चीन-तिब्बत युवा संवाद की मेजबानी की

tibet.net, २८ अगस्त, २०२३

वाशिंगटन डी सी। वाशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय ने न्यूयॉर्क स्थित चीनी युवा पहल-डेमोक्रेसी सैलून-के सहयोग से २६ अगस्त २०२३ को तिब्बत हाउस में 'चीन-तिब्बत युवा इंटरैक्शन' कार्यक्रम के तहत एक फिल्म चर्चा का आयोजन कराया। इस कार्यक्रम में तिब्बती समुदाय और न्यूयॉर्क और आसपास के क्षेत्रों में चीनी समुदाय से लगभग



५० युवा शामिल हुए। प्रतिभागियों ने प्रसिद्ध तिब्बती फिल्म निर्माता स्वर्गीय पेमा छेतेन द्वारा निर्देशित फिल्म 'थारलो' देखी। डेमोक्रेसी सैलून के आयोजक व्हाइट पेपर रिवोल्यूशन यानी श्वेत पत्र क्रांति की भावना से प्रेरित हैं और उन्होंने ही तिब्बत पर फिल्म प्रदर्शन का विचार सुझाया था।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए तिब्बत कार्यालयमें कार्यरत चीनी संपर्क अधिकारी छुल्ट्रिम ग्यात्सो ने फिल्म चर्चा के माध्यम से चीन-तिब्बत युवा बातचीत की सराहना की। छुल्ट्रिम ने स्वर्गीय पेमा छेतेन की विरासत को याद किया और तिब्बत के अंदर समकालीन तिब्बती दुनिया के दैनंदिन के अनुभवों और संघर्षों को फिल्म निर्माण के माध्यम से उजागर करने में उनके अग्रणी योगदान का जोरदार तरीके से उल्लेख किया। उन्होंने इस तथ्य को भी याद दिलाया और उजागर किया कि फिल्मों में उन अनेक संघर्षों और समस्याओं का सीधे उल्लेख नहीं किया जाता है जिनके लिए चीनी अधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। छुल्ट्रिम ने परम पावन दलाई लामा के दृष्टिकोण और उनकी चार प्रमुख प्रतिबद्धताओं, २००९ के बाद से तिब्बत के अंदर आत्मदाह के १६० से अधिक मामलों और बीजिंग द्वारा थोपे गए नवीनतम चीनीकरण अभियान के तहत अनिवार्य आवासीय विद्यालयों में जाने के लिए मजबूर कर दिए गए लगभग दस लाख तिब्बती बच्चों सहित तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त जानकारी दी।

फिल्म दिखाने के बाद प्रतिभागियों को चर्चा के लिए-संस्कृति प्रतिनिधित्व, पहचान और जुड़ाव तथा सहानुभूति और समझ शीर्षक से तीन समूहों में विभाजित किया गया। प्रतिभागियों ने इन विषयों पर बारी-बारी से चर्चा की। अधिकांश चीनी युवा प्रतिभागी चीन की मुख्य भूमि से थे और उन्होंने फिल्म पर अपने विचार व्यक्त किए। उनमें से कई ने तिब्बत के विभिन्न हिस्सों की अपनी यात्राओं के अनुभवों को भी साझा किया। तिब्बती प्रतिभागी फिल्म में छिपे संदेशों पर भी विचार व्यक्त कर रहे थे और बर्बरचीनी नीतियों के तहत तिब्बत की स्थिति का परिचय दे रहे थे। इस तरह विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के साथ जीवंत चर्चा हुई और भविष्य में जोरदार सहयोग के लिए प्रतिबद्धता का सुझाव दिया गया।

## ◆ उत्तर बंगाल के सालुगाड़ा में तिब्बत समर्थक समूहों (टीएसजी) का सशक्तिकरण और नवीकरण

tibet.net, २९ अगस्त, २०२३

दिल्ली। भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) और तिब्बत पर कार्रवाई के लिए हिमालय समिति (हिमकैट) ने सिक्किम और उत्तर बंगाल में तिब्बत समर्थक समूहों (टीएसजी) के सशक्तिकरण और पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत तिब्बत समर्थक समूहों की बैठक आयोजित की। पश्चिम बंगाल के उत्तरी



हिस्से में अवस्थित सालुगाड़ा में २८ अगस्त, २०२३ को हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल स्कूल (एचबीसीएस) में यह बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़-इंडिया (सीजीटीसी-आई) के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में सीजीटीसी-आई के क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता जी उपस्थित थे। साथ ही संगठन के अन्य लोग शामिल हुए।

उपस्थित लोगों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधि, स्थानीय निवासी और स्कूल के वरिष्ठ छात्र शामिल थे। हिमकैट सिलीगुड़ी के सचिव और कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़ - इंडिया (सीजीटीसी-आई) के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक श्री सोनम लुंडुप ने हिमकैट और एचबीसीएस की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए मेहमानों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में सालुगाड़ा के आसपास सक्रिय विभिन्न तिब्बत समर्थक समूहों (टीएसजी) और तिब्बती गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग और समन्वय के महत्व पर जोर दिया।

श्री सौम्यदीप दत्ता ने भारत की सुरक्षा के साथ तिब्बती मुद्दे के नाभिनाल संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत पर चीनी अतिक्रमण के बाद भारत की सुरक्षा को खतरा, कैलाश-मानसरोवर जैसे हिंदू धर्मस्थलों की तीर्थयात्रा में बाधाएं पैदा की जाने लगीं। तिब्बत में गतिविधियों के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में प्रदूषण फैला और तिब्बती बौद्ध धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता पैदा हो गई है। उन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए तिब्बती मुद्दे को सांस्कृतिक चश्मे से देखने पर बल दिया।

आईटीसीओ के समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन ने भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) का परिचय दिया। उन्होंने अपने संबोधन में चीनी नीति को लेकर संयुक्त राष्ट्र की उसरिपोर्ट का खुलासा किया, जिसमें दस लाख तिब्बती बच्चों को चीनीकम्युनिस्ट शासन द्वारा संचालित अनिवार्य आवासीय विद्यालयों में जबरन भेजे जाने, तिब्बती संस्कृति, धर्म और भाषा को खतरे में डालने की खतरनाक साजिशें की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तिब्बत के साथ ऐतिहासिक संबंध और आत्मीयता के कारण हिमालयी लोगों पर तिब्बती मुद्दे का समर्थन करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है।

मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र कुमार जी ने तिब्बती मुद्दे के लिए भारत के ऐतिहासिक समर्थन को स्वीकार किया और जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत के राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों में तिब्बत मुद्देको शामिल करने और तिब्बत-समर्थक उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने का आग्रह किया। उन्होंने तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे से उत्पन्न मौजूदा सीमा चुनौतियों का जिक्र किया और तिब्बत और भारत के बीच ऐतिहासिक,

सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने १४वें दलाई लामा के नेतृत्व की प्रशंसा की और तिब्बती मुद्दे के लिए स्थानीय समर्थन का अनुरोध किया।

इस कार्यक्रम ने सिलीगुड़ी में हिमकैट की नई कार्य समिति कागठन किया

गया। कार्यक्रम का समापन नई समिति को सफल कार्यकाल के लिए आभार और शुभकामनाओं के साथ हुआ। इसके बाद गणमान्य व्यक्ति सालुगाड़ा से दार्जिलिंग के लिए प्रस्थान कर गए।

## ◆ दार्जिलिंग में भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) के नए चैप्टर का गठन

tibet.net, ३१ अगस्त, २०२३

**दार्जिलिंग।** भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) ने दार्जिलिंग के मंजूश्री सेंटर ऑफ तिब्बतन कल्चर (तिब्बती मंजूश्री संस्कृति केंद्र) में वहांके स्थानीय और तिब्बती समुदायों के साथ ३० अगस्त २०२३ को एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कोर ग्रुप फॉर तिब्बती कॉज़- इंडिया (सीजीटीसी-आई) के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार, विशेष अतिथि के तौर पर सीजीटीसी-आई के क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता, तिब्बत पर कार्रवाई के लिए हिमालयन समिति ( हिमकैट), सिलीगुड़ी के सचिव श्री सोनम लुंडुप लामा, सीजीटीसी-आईके पूर्व क्षेत्रीय संयोजक और दार्जिलिंग तिब्बती सेंटलमेंट की नवनियुक्त अधिकारी पेमा छेरिंग धेनमत्सांग की गरिमामय उपस्थिति रही। बैठक में स्थानीय समुदाय के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के स्थानीय अध्यक्ष श्री ग्युरमी टी. भूटिया ने बैठक में उपस्थित लोगों को कार्यक्रम के बारे में बताया और कार्यक्रम के आयोजन में आईटीसीओ के साथ मिलकर समन्वय किया।

मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र कुमार ने भारत-तिब्बत मैत्री संघ(आईटीएफएस) और कोर ग्रुप फॉर तिब्बती कॉज़- इंडिया (सीजीटीसी-आई)के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और विशेषकर स्थानीय हिमालयी समुदायों का समर्थन जुटाने के महत्व पर जोर दिया। तिब्बती मुद्दे को आगे बढ़ाने में आईटीएफएस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि वह तिब्बती मुद्दे का समर्थन करे और परम पावन १४वें दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। श्री सुरेंद्र कुमार ने दिल्ली में कोर ग्रुप की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें जी-२० शिखर सम्मेलन से पहले तिब्बत मुद्दे को लेकर पांच मांगों को रेखांकित किया गया था।

विशिष्ट अतिथि श्री सौम्यदीप दत्ता ने तिब्बती आंदोलन को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बताया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि तिब्बत के बारे में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी फैलाई जाए और आंदोलन जमीनी स्तर तक पहुंचाई जाए। उन्होंने जनता



को 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' से परिचित कराया और तिब्बत में बांधों के बड़े पैमाने पर विकास के कारण ब्रह्मपुल (यारलुंग छांगपो या सियांग) नदी परियोजना से उत्पन्न संभावित खतरों पर प्रकाश डाला।

श्री सोनम लुंडुप ने हिमकैट और इसकी गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न तिब्बती गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के बीच और अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

आईटीसीओ के समन्वयक थुपेन रिनज़िन ने आईटीसीओ के उद्देश्य और आईटीएफएस दार्जिलिंग चैप्टर की स्थापना के औचित्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने तिब्बती मुद्दे के लिए समर्थन जुटाने और तिब्बत समर्थक संगठनों को पुनर्जीवित करने के महत्व पर जोर दिया। थुपेन ने तिब्बत और हिमालयी राज्यों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला और यह स्पष्ट किया कि भारत-चीन मुद्दों का समाधान तिब्बती मुद्दे के समाधान में ही अंतर्निहित है। उन्होंने तिब्बत की गंभीर स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें आत्मदाह, भारी निगरानी और तिब्बती संस्कृति, धर्म और भाषा को खतरे में डालने वाले चीनी कम्युनिस्ट शासन द्वारा संचालित अनिवार्य आवासीय स्कूल शामिल हैं। उन्होंने आईटीएफएस-दार्जिलिंग को सामुदायिक भागीदारी का मंच बताते हुए स्थानीय समुदाय से इसके प्रति समर्थन बढ़ाने की अपील की।

इस कार्यक्रम में तिब्बत के प्रबल समर्थक स्वर्गीय प्रोफेसर कृष्ण नाथ की पुनर्मुद्रित पुस्तक-तिब्बत मुक्ति साधना और भारत-चीन संबंध-का विमोचन किया गया।

इस बैठक में सबसे अहम घटना आईटीएफएस-दार्जिलिंग चैप्टर का ऐतिहासिक गठन रहा। चैप्टर के नवगठित बोर्ड में सेंडुप डुकपा को अध्यक्ष, श्री सुभमोय चटर्जी और तिब्बती सेंटलमेंट अधिकारी को उपाध्यक्ष नामित किया गया। बोर्ड में ११ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। मुख्य कार्यक्रम के बाद एक समूह चर्चा का भी आयोजन किया गया, जहां आईटीएफएस के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार ने प्रश्नोत्तर सत्र के बाद नवगठित समिति को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताया और मार्गदर्शन किया।

श्री सुरेंद्र कुमार और आईटीएफएस-दार्जिलिंग के महासचिव श्री ग्युरमी टी. भूटिया ने भी कार्यक्रम के बाद स्थानीय प्रेस से बातचीत की।

अगले दिन संभूता तिब्बती स्कूल, दार्जिलिंग के सभागार में स्थानीय तिब्बती समुदाय के साथ विशेष रूप से इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री सुरेंद्र कुमार ने जनता को आईटीएफएस, सीजीटीसी-आई और तिब्बतियों को मिले ऐतिहासिक

समर्थन के बारे में जानकारी दी।

दार्जिलिंग की तिब्बती सेंटलमेंट अधिकारी पेमा छेरिंग धेनमात्संग ने आईटीएफएस और आईटीसीओ की पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं और इसके सदस्यों को खटक देकर सम्मानित किया।

आईटीसीओ समन्वयक थुप्रेन रिनज़िन ने भारत में, विशेष रूप से हिमालयी समुदायों के भीतर तिब्बत समर्थक समूहों को मजबूत करने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आईटीएफएस-दार्जिलिंग चैप्टर के गठन के औचित्य और स्थानीय समुदायों के भीतर तिब्बती मुद्दे के लिए बढ़ते समर्थन के संभावित प्रभाव की गहराई से पड़ताल की। उन्होंने स्थानीय तिब्बती समुदाय और तिब्बती गैर सरकारी संगठनों से आईटीएफएस-दार्जिलिंग की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और समर्थन करने की अपील की।

आईटीएफएस-दार्जिलिंग के प्रथम अध्यक्ष श्री सेंडुप डुक्या ने स्थानीय तिब्बती समुदाय से सहयोग और समर्थन की अपील की और भविष्य में भी सहयोग के बिंदुओं को तलाशने के लिए विभिन्न स्थानीय तिब्बती गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने की योजना के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आईटीएफएस दार्जिलिंग तिब्बती मुद्दे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा।

आईटीसीओ समन्वयक थुप्रेन रिनज़िन ने कहा, 'मैं कार्यक्रम को शानदार ढंग से सफल बनाने में सहयोग और समर्थन के लिए तिब्बती मुक्ति साधना के स्थानीय अध्यक्ष श्री ग्युरमी टी. भूटिया और तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी सुश्री पेमा छेरिंग धेनमात्संग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।' आईटीसीओ के उप समन्वयक तेनज़िन जॉर्डन ने कहा, 'दार्जिलिंग में आयोजित यह कार्यक्रम सिक्किम और उत्तर बंगाल में तिब्बत समर्थक समूहों को मजबूत और पुनर्जीवित करने के हमारे व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि यह स्थानीय समुदाय के बीच अधिक जागरूकता पैदा करेगा।' बैठक का समापन भारतीय और तिब्बती राष्ट्रगान के साथ हुआ। दोपहर बाद आगत अतिथिगण कालिम्पोंग के लिए रवाना हो गए।

## ◆ कलिम्पोंग में तिब्बत समर्थक समूह को मजबूत करने के लिए सीजीटीसी-आई और आईटीसीओ का अभियान

tibet.net, ३१ अगस्त, २०२३

**कालिम्पोंग।** तिब्बत मुक्ति साधना को तेज करने और फिर से प्रज्वलित करने के उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण समय में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया (सीजीटीसी-आई) भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) के साथ मिलकर अपना दौरा अभियान चला रहा है। अभियान के दौरान इसके सदस्य उत्तर बंगाल और सिक्किम के तिब्बत समर्थक समूहों से मिलेंगे और तिब्बती आंदोलन के लिए इन क्षेत्रों में सक्रिय तिब्बती समुदायों के साथ समन्वय में काम करने के लिए बात करेंगे।

३१ अगस्त २०२३ को गए सीजीटीसी-आई के प्रतिनिधिमंडल में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया (सीजीटीसी-आई) के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार और सीजीटीसी-आई के क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता, हिमालयन कमेटी फॉर एक्शन ऑन तिब्बत (हिमकैट), सिलीगुड़ी के सचिव श्री सोनम लुंडुप लामा और सीजीटीसी-आई के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक शामिल थे। इनके साथ गए भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) के समन्वयक थुप्रेन रिनज़िन और उप समन्वयक तेनज़िन जॉर्डन ने परम पावन १४वें दलाई लामा के बड़े भाई और कसूर (पूर्व तिब्बती कैबिनेट) के सदस्य ग्यालो धुंडोप से कलिम्पोंग में उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने, लंबे समय से तिब्बत समर्थक और भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) कलिम्पोंग के अध्यक्ष पी.टी.भूटिया से भी मुलाकात की।

दोपहर बाद भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) ने भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) कलिम्पोंग के सहयोग से मुख्य अतिथि



श्री सुरेंद्र कुमार और विशेष अतिथि श्री सौम्यदीप दत्ता, श्री सोनम लुंडुप लामा, कलिम्पोंग तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी कर्मा गेलेक सहित अन्यकी उपस्थिति में कलिम्पोंग के मणि लाखांग में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय और तिब्बती समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईटीएफएस कलिम्पोंग के चुंगडक ने कार्यक्रम के बारे में बताया और विवरण पढ़ा। कलिम्पोंग के तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी कर्मा गेलेक ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और तिब्बत की वर्तमान स्थिति से लोगों को अवगत कराया और तिब्बत केहित में व्यक्तिगत योगदान की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुमार ने आईटीएफएस के लक्ष्य, उद्देश्य और पृष्ठभूमि का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अपनी तिब्बत नीति को पुनर्निर्धारित करना चाहिए और आईटीएफएस इस संबंध में भारत सरकार से अपील करना जारी रखेगा। उन्होंने परम पावन १४वें दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए चीनी सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने तिब्बत की आजादी के लिए आह्वान किया और रेखांकित किया कि तिब्बत पर चीन के कब्जे से भारत और उसके हिमालयी समुदायों के लिए किस तरह से खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने चीन द्वारा तिब्बत में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, व्यापक तौर पर सैन्य बुनियादी ढांचे और बांध निर्माण के कारण सुरक्षा पर उत्पन्न खतरों की ओर भी इशारा किया। आईटीसीओ समन्वयक थुप्रेन रिनज़िन ने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की पृष्ठभूमि और भारत में तिब्बत समर्थक समूह, विशेषरूप से हिमालयी समुदायों को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने तिब्बत की वर्तमान स्थिति और औपनिवेशिक आवासीय विद्यालयों



सहित तिब्बत में चीनी सरकार द्वारा अपनाई गई बर्बर नीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्थानीय तिब्बती समुदाय से आईटीएफएस, कलिम्पोंग की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और समर्थन करने की भी अपील की। उन्होंने आईटीएफएस कलिम्पोंग को आईटीसीओ की ओर से कलिम्पोंग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन भी दिया।

बैठक में आईटीएफएस कलिम्पोंग की क्षेत्रीय कार्य समिति के चुनाव १५ दिनों के भीतर कराने की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय और तिब्बती दोनों समुदायों के प्रमुख सदस्यों ने कलिम्पोंग में तिब्बत के लिए समर्थन बढ़ाने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।

## ◆ सांसद मिग्युर दोरजी और लोबसांग ग्यात्सो सिथर ने केरल के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की

tibet.net, २४ अगस्त, २०२३

केरल तिब्बत के समर्थन में पक्ष रखने के लिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में २३ अगस्त २०२३ को मौजूद निर्वासित तिब्बती सांसद मिग्युर दोरजी और लोबसांग ग्यात्सो सिथर ने केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयनसे मुलाकात की।

बैठक में सांसद ने मुख्यमंत्री को निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा राज्य स्तर पर चलाए जानेवाले पक्षधरता कार्यक्रम के उद्देश्य, तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति और चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के चीनीकरण नीतियों के बारे में जानकारी दी। सांसदों ने उन्हें स्मृति चिन्ह और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष का अपील-पत्र भेंट किया।

दोपहर में सांसदों ने केरल विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ए.एन. शमसीर से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्षको सांसदों ने अपनी यात्रा का उद्देश्य साझा किया और उन्हें तिब्बत के अंदर की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। सांसदों ने अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष का अपील-पत्र प्रस्तुत किया। बैठक के बाद स्पीकर के प्रोटोकॉल अधिकारी ने तिब्बती सांसदों को केरल विधानसभा का अवलोकन कराया।

## ◆ तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की

tibet.net, २७ अगस्त, २०२३

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों- यूडन औकात्सांग, गेशे मोनलम थारचिन और ताशी धोंडुप के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से शिष्टाचार भेंट करके सिक्किम में तिब्बत के पक्ष में अभियान शुरू की। तिब्बती सांसदों के २६ अगस्त को सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचने पर एलटीए अध्यक्ष जिनपा फुंटसोक, टीएसओ लखपा छेरिंग और तिब्बती संघों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राज भवन में सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से शिष्टाचार भेंट की।

सांसदों ने राज्यपाल से तिब्बत में रहने वाले और सिक्किम में रहने वाले तिब्बतियों के लिए समर्थन की अपील की। उन्होंने निर्वासित तिब्बती संसद (टीपीआईई) की ओर से स्मृति चिन्ह और दस्तावेज भेंट किए। राज्यपाल ने कहा कि वह चीन-तिब्बत संघर्ष के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्हें एक दशक पहले पूर्व कालोन ट्रीपा प्रोफेसर समदोंग रिनपोछे को सुनने का अवसर मिला था और उन्होंने वाराणसी में केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान का भी दौरा किया है जो उनके पैतृक स्थान के करीब ही है।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि भारत की केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछले ६० वर्षों से अधिक समय से निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों को आवश्यक सहायता प्रदान की है और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई है। भारत तिब्बतियों के समर्थन में आगे भी आवश्यक कार्य करना जारी रखेगा। तिब्बत की विशिष्ट संस्कृति और धर्म के संरक्षण के बारे में राज्यपाल ने तिब्बती सांसदों को तिब्बत पर पुस्तकों और संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों और सिक्किम सरकार के नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआईटी) में सोवा रिग्पा के अध्ययन के बारे में बताया।

तिब्बत के प्रति अपनी चिंता और समर्थन व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने आगे कहा कि वह सिक्किम में परम पावन दलाई लामा का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि वह निकट भविष्य में धर्मशाला का दौरा करने की उम्मीद कर रहे हैं।

तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। निर्वासित तिब्बती संसद की ओर से उन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-३ की सफल लैंडिंग के लिए भारत को हार्दिक बधाई दी। परमपावन दलाई लामा और टीपीआईई के अध्यक्ष भारत की उल्लेखनीय सफलता पर भारतीय प्रधानमंत्री को पहले ही बधाई दे चुके हैं।

यात्रा के दौरान तिब्बती सांसदों के साथ गंगटोक टीएसओ लखपा छेरिंग भी थे और यात्रा के बाद सांसदों को श्री ताशी द्वारा 'तिब्बत' का अवलोकन कराया गया। यह 'तिब्बत' सिक्किम राजभवन में एक कमरा है, जो राज्य की यात्रा के दौरान परम पावन दलाई लामा के लिए आरक्षित है। श्री ताशी तिब्बती मूल के कर्मचारी हैं और राजभवन में कार्यरत हैं।

## ◆ तिब्बत पर चीन का दावा गलत, इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास: जनरल नरवणे ने तिब्बती मुक्ति साधनाका समर्थन किया

(दिल्ली में छठे अंतरराष्ट्रीय रंगज़ेन (स्वतंत्रता) सम्मेलन में पूर्व सेना प्रमुख ने चीन को निशाने पर लेते हुए कहा कि दुनिया भर में तिब्बतियों को अपनी मातृभूमि पर लौटने का वैध अधिकार है)

theprint.in, १६ अगस्त, २०२३

नई दिल्ली। चीन से स्वतंत्र होने के लिए तिब्बत की मुक्ति साधना को रेखांकित करते हुए भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (सेवानिवृत्त) ने बुधवार को कहा कि दुनिया भर में तिब्बतियों को अपनी मातृभूमि पर लौटने और अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ जीने का वैध अधिकार है। वह दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में छठे अंतरराष्ट्रीय रंगज़ेन (स्वतंत्रता) सम्मेलन में बोल रहे थे। इस अवसर पर निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधि गेशे लहरम्पा बावा लोबसांग पेंडे और प्रसिद्ध उग्यूर स्वतंत्रता सेनानी उमित हमित शामिल थे।

जनरल नरवणे ने कहा, तिब्बत में ६० लाख तिब्बती रहते हैं जबकि १,४०,००० निर्वासन में रह रहे हैं। इनमें से १,००,००० भारत में हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या शक्ति का असाधारण अज्ञात भंडार है, जिसका दोहन करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, 'यह वास्तव में ऐतिहासिक तथ्य है कि तिब्बत भारत का पड़ोसी रहा है और है। दोनों देशों के बीच सीमा खुली और शांतिपूर्ण थी। इससे न केवल व्यापार और लोगों की मुक्त आवाजाही की सुविधा मिलती थी, बल्कि मानव सभ्यता के बेहतरीन विचारों का प्रवाह भी होता था।'

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि सैद्धांतिक पंचशील समझौते की एक धारा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को लेकर थी। इस धारा के परिणामस्वरूप तिब्बत पर चीनी आक्रमण के समय कुछ न बोलने की अस्पष्ट नीति बन गई थी। बता दें कि पंचशील समझौता १९५४ में भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षरित सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों पर आधारित एक संधि थी। उन्होंने कहा कि चीन ने दशकों से तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और क्षेत्रीय और प्रशासनिक परिवर्तन किए हैं जो तिब्बतियों की पहचान और संस्कृति को बदल देनेवाले हैं।

जनरल नरवणे ने आगे कहा कि चीन द्वारा जारी ताजा श्वेत-पत्र में दावा किया गया है कि तिब्बत प्राचीन काल सेयानी सातवीं शताब्दी से चीन का हिस्सा रहा है, जो अपने आप में 'गलत है और इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास' है।

उन्होंने तिब्बती मुद्दे की मदद करने के लिए 'ऊर्ध्वाधर एकीकरण' और 'क्षैतिज विस्तार' के दो तरफा दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव दिया। 'ऊर्ध्वाधर एकीकरण' दृष्टिकोण को समझाते हुए उन्होंने कहा कि इसमें विचारकों और थिंक टैंकों को शामिल करके संयुक्त राष्ट्र सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से विश्व स्तर पर तिब्बत मुद्दे को उठाया जाना चाहिए।

उन्होंने 'क्षैतिज विस्तार' को समझाते हुए कहा कि इसके तहत आंदोलन की गति को बनाए रखने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट किया जाएगा। इस दृष्टिकोण को दुनिया भर में सामूहिक आवाज़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रंगज़ेन आंदोलन गतिशील और प्रभावशाली बना रहे।

व्याख्यान के दौरान उन्होंने कई बार चीन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने चीन के दृष्टिकोण की तुलना भारत से करते हुए कहा, 'भले ही चीन की ताकत बढ़ गई है, लेकिन इसी ताकत में उसकी कमजोरियां छिपी हुई हैं। चीन दबाव और भय को आधार बनाकर काम करता है जबकि भारत

सहयोग और विश्वास बनाने के साथ काम करता है।'

उन्होंने कहा कि चीन की बदमगजी तिब्बत, ताइवान, झिंझियांग और यहां तक कि मंगोलिया तकपर चल रही है। चीन की ग्रे जोन कार्रवाइयों को पहचानना भी जरूरी है। इसके तहत चीन अपनी साइबर ताकत और सूचना प्रसारित करने की क्षमताओं का लाभ उठाकर अपने अनकूल के ऐतिहासिक संदर्भों को प्रसारित करता है, नक्शे में हेरफेर करता है और अपनी कपटपूर्ण चालों को कानूनी जामा पहनाता है। इसे कई बार सक्रिय रूप से किया जाता है तो कई बार गुपचुप तरीके का सहारा लिया जाता है।

इसलिए उन्होंने कहा कि अब 'हिन्द- प्रशांत संरचना का एक नया आकार विकसित करने की जरूरत' है।

चीन द्वारा विवादित क्षेत्रों में गांवों को बसाने के बारे में बोलते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि विवादित क्षेत्रों में 'ज़ियाओकांग' (मध्यम रूप से समृद्ध) गांवों का निर्माण, भूमि-सीमा कानून की घोषणा और क्षेत्र के देशों का जबरदस्ती शोषण इस बात को रेखांकित करता है कि इस मुद्दे को लेकर गहन जांच और मजबूत प्रतिक्रिया की तात्कालिक आवश्यकता आन पड़ी है।

उन्होंने सुझाव दिया कि चीन की इन कार्रवाइयों का 'प्रभावी ढंग से मुकाबला करने' के लिए राजनयिक, कानूनी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को शामिल करते हुए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चीन के आधिपत्य को नियंत्रित करने के लिए हांगकांग और ताइवान के वित्तीय केंद्रों सहित दक्षिण एशियाई देशों को ध्यान में रखते हुए एक नई हिन्द-प्रशांत संरचना को आकार देने की आवश्यकता है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रमुख शक्तियां आज चीन का मुकाबला करने के लिए इच्छुक दिखाई देती हैं। जबकि अमेरिका-चीन के बीच प्रतिस्पर्धा हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। भारत आज वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर उभरा है और चीन द्वारा एकतरफा रूप से 'यथास्थिति' को बदलने के प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि गलवान घटना के बाद भारत ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रयासों को तेज कर दिया है और चीन के किसी भी नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए अपनी सेना को नए सिरे से तैयार कर लिया है।

जनरल नरवणे ने कहा कि २००८ में बीजिंग ओलंपिक से पहले हुए विरोध-प्रदर्शनों ने तिब्बत में समृद्धि और स्वतंत्रता की झूठी छवि पेश करने के चीनी दुष्प्रचार को उजागर कर दिया। इससे तिब्बतियों का साहस और दृढ़ संकल्प उजागर हुआ जो तिब्बत के लोगों की छिपी हुई शक्ति का संकेत है।

उन्होंने कहा कि विकास का चीनी मॉडल का प्रचार बेनकाब हो गया है और उसके दमन की असलियत सामने आ गई है। इन विरोध-प्रदर्शनों ने दुनिया को बताया कि तिब्बत दशकों के चीनी दमन के बावजूद तिब्बत मुद्दा जीवित है। पूर्व सेना प्रमुख ने तिब्बत को पारिस्थितिक बफर भी कहा क्योंकि यह पारिस्थितिक सुरक्षा से संबंधित है।

## IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.

Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.

You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.

We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

**Thupten Rinzin**

Coordinator  
India Tibet Coordination Office

## आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।

तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और कूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।

आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नहीं रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।

इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे हैं। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमें तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीचे लिखे गये पता या ई-मेल पर भेज सकते है।

अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमें समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

थुप्तेन रिन्ज़ीन

समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र  
नई दिल्ली

कार्यलय पता: भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच-10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर-03, नई दिल्ली-110024

फोन: 011-29830578

ई-मेल: coordinator@indiatibet.net

# रणनीतिक बैठक मे शामिल भारतीय और तिब्बतिया सांसद ।



1: तिब्बत के लिए सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच के संयोजक सांसदश्री सुजीत कुमार



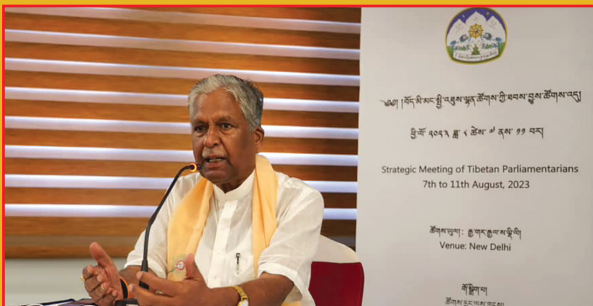
2: लोकसभा सांसद के श्री राजेंद्र अग्रवाल



3: राज्यसभा सदस्य श्री ए.डी. सिंह



4: राज्यसभा सांसद श्री अनिल हेगड़े



5: राज्यसभा सांसद डॉ अशोक बाजपेयी



6: पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन